राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान

*364. **डा० भाई महावीर :**
श्री लाल आडवाणी :

क्या **शिक्षा तथा युवा सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान में आवश्यकता से अधिक स्टाफ है और वहां बहुत से रीडरों तथा लेक्चररों के पास शिक्षण सम्बन्धी कोई काम नही है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस संस्थान द्वारा तथाकथित कर्मशालाओं और विचार-गोष्ठियो के आयोजन पर सार्वजनिक धन की बरबादी की किन्हीं शिकायतों की ओर दिलाया गया है;

(ग) पिछले वर्ष ऐसी कितनी कर्मशालाओ/विचार-गोष्ठियों का आयोजन किया गया और उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) सार्वजनिक धन की बरबादी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे है ?

†[NATIONAL INSTITUTE OF EDUCATION

*364. DR. BHAI MAHAVIR :
SHRI LAL K. ADVANI :

Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the National Institute of Education is overstaffed and quite a number of Readers and Lecturers have no teaching assignment;

(b) whether Government's attention has been drawn to any complaints of wastage of public funds on so called workshops and seminars organised by the Institute;

(c) the number of such workshops/seminars organised during the last year and the amount spent on them; and

(d) the steps being taken by Government to put an end to wastage of public funds ?]

शिक्षा तथा युवा सेवा मंत्री (प्रो० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी नहीं । संस्थान के मुख्य कार्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण है । कोई शिक्षण कार्य नही सौपा गया है क्यों कि क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों की तरह राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान में नियमित पाठ्यक्रम आयोजित नही किये जाते है ।

(ख) वर्कशापों और सेमिनारों पर धन की बरबादी के सम्बन्ध में सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है । तथापि, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के कामकाज के बारे में जांच करने के लिये 1968 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त पुनर्विलोकन समिति ने कहा था कि कुछ कार्यक्रम राज्य, क्षेत्रीय अथवा स्थानीय स्तरों पर आयोजित किये जा सकते हैं । समिति की राय में सेमिनारों और वर्कशापों के विद्यमान कार्यक्रम बहुत अधिक थे और उनमें से कुछ राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विकास कार्यक्रमों के साथ निकटता से जुड़े हुए प्रतीत नहीं हुए । की जाने वाली तैयारियां अक्सर अपर्याप्त थीं और प्राप्त स्तर अवसर पूरे नहीं होते थे ।

(ग) 1969-70 में 83 वर्कशाप और सेमिनार आयोजित किये गये और उन पर 5,36,000 रु० खर्च किये गये ।

(घ) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा सेमिनारों और वर्कशापों की संख्या कम करने तथा केवल ऐसे वर्कशापों अथवा सेमिनार आयोजित करने के

†[ ] English translation.

लिये कार्यवाई की जा रही है जो उनके कार्यक्रमों के विकास से सीधे ही सम्बंधित हों तथा पर्याप्त तैयारियों के साथ किये जाए ।

†[THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (PROF.V.K. R. V. RAO) : (a) to (d) A statement is laid on the Table of the Sabha.

STATEMENT

(a) No, Sir. The main functions of the Institute are educational research and training. There are no teaching assignments, as regular courses are not conducted at the National Institute of Education as in the Regional College of Education.

(b) Government have received no reports of wastage of funds on workshops and seminars. The Review Committee appointed by the Government of India in 1968 to look into the working of the National Council of Educational Research and Training, however, stated that some of the programmes can be conducted at State, regional or local levels. The Committee found the existing programme of seminars and workshops as very large and some of them did not appear to be linked closely with the developmental programmes of the National Institute of Education. The preparations made were often inadequate and standards maintained often left much to be desired.

(c) The number of workshops and seminars arranged in 1969-70 was 83 and the amount spent was Rs. 5,36,000/-.

(d) Action is being taken by the National Council of Educational Research and Training for reducing the number of seminars and workshops and for arranging only such workshops or seminars which are directly related to the development of their programmes and with adequate preparations.]

बेरोजगार इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को आर्थिक सहायता देने और उनके प्रशिक्षण की योजनाएं

*365. **श्री सूरज प्रसाद** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेरोजगार इंजीनियर तथा तकनीशियनों को आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित योजनाएं कब से आरम्भ की गई हैं;

(ख) अब तक कितने इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को सहायता दी जा चुकी है; और

(ग) इन योजनाओं के अधीन दी गई धनराशि कितनी अवधि के अन्दर लौटाई जानी है और उस पर लिये जाने वाले ब्याज की दर क्या है ?

†[SCHEMES FOR FINANCIAL ASSISTANCE AND TRAINING OF THE UNEMPLOYED ENGINEERS AND TECHNICIANS

*365. SHRI SURAJ PRASAD : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the time since when the schemes sponsored by the Central and State Governments to provide financial assistance and training to the unemployed engineers and technicians have been given effect to;

(b) the number of engineers and technicians who have so far been given assistance; and

(c) the period within which the amounts given under these schemes are to be returned and the rate of interest charged thereon ?]

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामस्वामी) : (क) मई, 1968 में केन्द्रीय सरकार ने इंजीनियरों और तकनीशियनों को आर्थिक सहायता तथा प्रशिक्षण देने के उपायों समेत इंजीनियरों के लिए नियोजन अवसरों में वृद्धि के लिए अनेकों उपाय आरम्भ किये थे ।

(ख) उन इंजीनियरों की कुल संख्या सही-सही ज्ञात नहीं है जिन्होंने सरकार से सहायता प्राप्त की है ।

†[ ] English translation.